



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
जनसंपर्क कार्यालय
PUBLIC RELATIONS OFFICE



कानून के अंतर्गत बच्चों की सुरक्षा, देखरेख, बचाव जरूरी : प्रो. तिवारी
हिंदी विधि के विधि विभाग में 'कानून की नज़र में बच्चे' पर हुआ विशिष्ट व्याख्यान



वर्धा, 09 जनवरी, 2025 : महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के विधि विभाग में 'कानून की नज़र में बच्चे' विषय पर विशिष्ट व्याख्यान में जेएलए विश्वविद्यालय, इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, मथुरा के प्रो. ओंकार नाथ तिवारी ने कहा कि बच्चों को उनकी सुरक्षा, देखरेख और बचाव के लिए कानूनी प्रावधानों की जानकारी देना आवश्यक है। वे मंगलवार, 07 जनवरी को आयोजित व्याख्यान में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 और एकीकृत बाल संरक्षण योजना इसी दिशा में किए गए प्रावधान हैं। इस व्यवस्था के तहत बनाए गए आवासीय, देखरेख और सुधार गृहों से यह अपेक्षा की जाती है कि वहां बच्चे न केवल सुरक्षित रहेंगे बल्कि उनके

लिए एक वैकल्पिक परिवार के रूप में भी कार्य करेंगे और उनकी भावनात्मक, शारीरिक तथा व्यक्तित्व-विकास से जुड़ी आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी। उन्होंने बालकों की देखरेख और संरक्षण से संबंधित किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के प्रावधानों पर चर्चा की।

स्वागत वक्तव्य में विधि विद्यापीठ के अधिष्ठाता प्रो. जनार्दन कुमार तिवारी ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और विभिन्न विधियों में वर्णित प्रावधानों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन डॉ. दिव्या शुक्ला ने किया तथा डॉ. परमानन्द राठौर ने आभार माना। इस अवसर पर आनन्द भारती सहित विधि विभाग के विद्यार्थी उपस्थित रहे।

कायद्यानुसार मुलांची सुरक्षा, देखरेख, संरक्षण आवश्यक : प्रो. तिवारी

हिंदी विश्वविद्यालयाच्या विधी विभागात 'कायद्याच्या नजरेत मुले' विषयावर विशेष व्याख्यान

वर्धा, ०९ जानेवारी २०२५: महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालयाच्या विधी विभागात 'कायद्याच्या नजरेत मुले' या विषयावर विशेष व्याख्यानात जेएलए विश्वविद्यालय, इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, मथुरा येथील प्रो. ओंकार नाथ तिवारी म्हणाले की मुलांना त्यांची सुरक्षा, देखरेख आणि संरक्षणासाठी असलेल्या कायदेशीर तरतुदींबद्दल माहिती देणे आवश्यक आहे. ते मंगळवार, ७ जानेवारी रोजी आयोजित व्याख्यानात बोलत होते. बाल न्याय कायदा 2015 आणि एकात्मिक बाल संरक्षण योजना यात विविध तरतुदी केल्या आहेत. या प्रणालीअंतर्गत बांधण्यात येणारी सुधारगृहे केवळ मुलांना सुरक्षितता प्रदान करतीलच असे नाही तर त्यांच्यासाठी पर्यायी कुटुंब म्हणून काम करतील आणि त्यांच्या भावनिक, शारीरिक आणि व्यक्तित्व विकासाशी संबंधित गरजा पूर्ण करतील असे ही ते म्हणाले.

स्वागत भाषणात विधी विद्यापीठाचे अधिष्ठाता प्रो. जनार्दन कुमार तिवारी यांनी बाल न्याय कायदा, २०१५ आणि विविध कायद्यांमध्ये नमूद केलेल्या तरतुदींवर प्रकाश टाकला. कार्यक्रमाचे संचालन डॉ. दिव्या शुक्ला यांनी केले तर डॉ. परमानन्द राठोड यांनी आभार मानले. यावेळी आनंद भारती यांच्यासह विधी विभागाचे विद्यार्थी उपस्थित होते.